नईदुनिया

दिल्ली में सीजन की सबसे खराब हवा, नई पाबंदियाँ लागू

वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 पर पहुंचा; पार्किंग शुल्क बढ़ेगा, सरकारी कार्यालयों के समय में बदलाव और खुले में कचरा जलाने पर रोक

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार को इस मौसम की सबसे खराब वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण उपायों के दूसरे चरण की पाबंदियां तत्काल लागू कर दीं।

लोगों से निजी वाहनों का उपयोग कम करने, सार्वजनिक परिवहन और साझा वाहन व्यवस्था अपनाने की अपील की गई है। धूल और धुआं पैदा करने वाली निर्माण गतिविधियों से बचने तथा जिन लोगों का काम अनुमति देता है, उन्हें घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

सोमवार को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 324 दर्ज किया गया, जो अत्यंत खराब श्रेणी में है। आयोग की उपसमिति की बैठक में बताया गया कि पिछले 72 घंटों में वायु गुणवत्ता तेजी से बिगड़ी है। शनिवार को सूचकांक 117 था, जो मध्यम श्रेणी में आता है। रविवार को यह 261 पहुंचकर खराब श्रेणी में आया और सोमवार को 324 के साथ अत्यंत खराब स्तर पर पहुंच गया। मौसम की स्थिति बिगड़ने से प्रदूषण बढ़ा है।

दूसरे चरण के साथ पहले चरण की पाबंदियां भी जारी रहेंगी। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में नगर निगमों, यातायात पुलिस तथा प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

भारी यातायात वाले मार्गों और जाम प्रभावित स्थानों पर रोजाना यांत्रिक या निर्वात सफाई की जाएगी।

धूल दबाने वाले पदार्थ मिलाकर पानी का छिड़काव भी होगा। ये काम यातायात के अधिक दबाव वाले समय से पहले प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। प्रदूषण प्रभावित चिन्हित क्षेत्रों और निर्माण तथा तोड़फोड़ स्थलों पर जांच बढ़ाकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पार्किंग शुल्क बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली सरकार और संबंधित राज्य सरकारें दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर में सरकारी कार्यालयों और नगर निकायों के कर्मचारियों के कामकाज के समय में बदलाव कर रही हैं।



आयोग ने आवासीय कल्याण संघों को सुरक्षा गार्डों, सफाई कर्मचारियों और बागवानी कर्मचारियों के लिए बिजली के हीटर उपलब्ध कराने को कहा है। इसका उद्देश्य ठंड के दौरान खुले में जैविक पदार्थ या नगर निकाय का ठोस कचरा जलाने से रोकना है। आयोग ने लोगों से प्रदूषण कम करने के प्रयासों में सहयोग की अपील की है।

अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने पर विचार, जल्द हो सकती है घोषणा

- स्थायी भर्ती के अलावा कुछ जवानों को अतिरिक्त समय देने की तैयारी, चयन प्रक्रिया जारी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीरों को स्थायी सेवा में शामिल करने के अलावा कुछ जवानों को अतिरिक्त समय देने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। इस प्रस्ताव पर पिछले कुछ दिनों में कई उच्चस्तरीय बैठकें हो चुकी हैं। हालांकि, अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अग्निवीरों का चार वर्ष का कार्यकाल जल्द पूरा होने वाला है। भारतीय नौसेना के पहले बैच की सेवा 21 नवंबर को समाप्त होगी। इसके बाद वायुसेना के अग्निवीरों का कार्यकाल 21 दिसंबर और थलसेना के अग्निवीरों का कार्यकाल 31 दिसंबर को पूरा होगा। वर्तमान व्यवस्था के तहत अग्निपथ योजना में भर्ती युवा चार वर्ष तक सशस्त्र बलों में सेवा देते हैं। इनमें से अधिकतम 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने का प्रावधान है। इसके लिए चयन प्रक्रिया जारी है। चयन प्रदर्शन, पात्रता और संबंधित सेवा की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है।

सरकार अब उन अग्निवीरों को भी कुछ समय और सेवा में रखने की संभावना पर विचार कर रही है, जिन्हें नियमित सेवा में शामिल होने का अवसर नहीं मिल पाएगा। प्रस्ताव पर निर्णय होने की स्थिति में पहले बैच के कुछ जवानों को अतिरिक्त सेवा अवधि मिल सकती है।

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कुल 12.2 % की गिरावट

विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद पाँच राज्यों में 2.29 करोड़ मतदाता घटे

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में मतदाताओं की संख्या में करीब 2.29 करोड़ की कमी दर्ज की गई है।

इन पांच राज्यों में पुनरीक्षण से पहले लगभग 18.71 करोड़ मतदाता थे, जबकि अंतिम सूची में यह संख्या घटकर 16.43 करोड़ रह गई। यह कुल मतदाताओं में करीब 12.2 प्रतिशत की गिरावट है।

इन राज्यों में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की ओर से हाल में जारी आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कमी दर्ज की गई। यहां



मतदाताओं की संख्या 15.44 करोड़ से घटकर 13.40 करोड़ रह गई। इस तरह राज्य में करीब 2.04 करोड़ मतदाता कम हुए, जो पांचों राज्यों की कुल कमी का लगभग 90 प्रतिशत है।

उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 80 लाख से घटकर करीब 72 लाख रह गई। यहां लगभग 8 लाख मतदाताओं की कमी दर्ज की गई। पंजाब में मतदाता संख्या 2.15 करोड़ से घटकर 2.01 करोड़ रह गई। राज्य में करीब 14 लाख मतदाता कम हुए। मणिपुर में मतदाताओं की संख्या 20.9 लाख से घटकर 19.6 लाख रह गई।

यहां करीब 1.3 लाख की कमी दर्ज की गई। गोवा में मतदाता संख्या 11.85 लाख से घटकर 10.58 लाख रह गई। यहां करीब 1.27 लाख मतदाता कम हुए। पुनरीक्षण के दौरान प्रारूप सूची में हटाए गए कुछ नाम दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद अंतिम सूची में वापस जोड़े गए। उत्तर प्रदेश में प्रारूप सूची से हटाए गए करीब 84 लाख मतदाता अंतिम सूची में शामिल किए गए। निर्वाचन अधिकारियों के अनुसार, पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना है।

यूरोप के कई देशों में सुपरमार्केट के फ्रिज पर साइबर हमला

- तापमान 50 डिग्री, कई दुकानों में खाद्य सामग्री खराब, पिछले महीने भी हुआ था ऐसा हमला

यूरोप, एजेंसी: यूरोप के कई देशों में सुपरमार्केट के फ्रिज और फ्रीजर साइबर हमलों का निशाना बने हैं। बेल्जियम, लक्जमबर्ग, स्वीडन और एस्टोनिया में दुकानों की शीतलन प्रणालियों का तापमान अचानक बढ़ गया। कुछ स्थानों पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से खाद्य सामग्री खराब होने का खतरा पैदा हो गया।

बेल्जियम और लक्जमबर्ग में सुपरमार्केट संचालित करने वाली कंपनियों अहोल्ड डेलहाइज और कोलरुइट ने सोमवार को बताया कि रात के दौरान हुए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी हमले से कई दुकानों के फ्रिज और फ्रीजर प्रभावित हुए।

डेलहाइज की प्रवक्ता के अनुसार, शीतलन प्रणालियों में तापमान बढ़ने का पता चला है और मामले की जांच की जा रही है। बेल्जियम की शीतलन प्रणाली कंपनी सबकोबेल के प्रमुख



स्टीफन मोएलन्स ने बताया कि हमलावरों ने उपकरणों को पिघलाव प्रक्रिया में डाल दिया था। इससे फ्रिज और फ्रीजर का तापमान बढ़ गया। स्वीडन में भी कई दुकानों की शीतलन प्रणालियां प्रभावित हुईं। देश के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र ने ऐसे मामलों की जांच शुरू की है। सुपरमार्केट श्रृंखला आईसीए के एक स्टोर ने बताया कि उसके फ्रिज और फ्रीजर का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। कॉप श्रृंखला के छह स्टोर भी प्रभावित हुए।

एस्टोनिया में एक सुपरमार्केट की शीतलन प्रणाली का तापमान भी 50 डिग्री तक पहुंचने की जानकारी सामने आई है। तकनीकी सेवा प्रदाता के अनुसार, हमले के बाद समस्या को कुछ ही समय में नियंत्रित कर लिया गया। इससे पहले अक्टूबर में फ्रांस के सैकड़ों सुपरमार्केट की शीतलन प्रणालियों पर साइबर हमला हुआ था।

वहां तापमान बढ़ने से खाद्य सामग्री खराब हुई और कुछ स्थानों पर आग लगने की घटनाएं भी हुईं। फिलहाल इन हमलों के पीछे किसका हाथ है, यह स्पष्ट नहीं है। किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है।

पीएम नेतन्याहू आइजनकोट के साथ सरकार बनाने को तैयार



- अरब दलों के समर्थन से विपक्ष को बहुमत मिलने की संभावना; चुनाव में किसी गठबंधन को नहीं मिला स्पष्ट जनादेश

तेल अवीव, एजेंसी: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू विपक्षी नेता गादी आइजनकोट के साथ मिलकर सरकार बनाने को तैयार हैं। इजराइली समाचार माध्यम आई24 न्यूज के मुताबिक, नेतन्याहू को आशंका है कि आइजनकोट अरब पार्टियों के समर्थन से वैकल्पिक सरकार बना सकते हैं। इससे उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ सकती है। इसी कारण नेतन्याहू ने आइजनकोट के साथ गठबंधन की संभावना खारिज नहीं की है। हालांकि, आइजनकोट ने इस प्रस्ताव पर अब तक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

रविवार को जॉइंट लिस्ट और राअम जैसी अरब पार्टियों ने आइजनकोट को समर्थन देने की घोषणा की थी। इससे उन्हें 67 सांसदों का साथ मिलने की संभावना है। इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। 120 सदस्यीय संसद में सरकार बनाने के लिए 61 सीटें जरूरी हैं। नेतन्याहू समर्थित गठबंधन को 53, आइजनकोट के विपक्षी गठबंधन को 48 और अरब पार्टियों को 19 सीटें मिली हैं।

नेतन्याहू के सामने सरकार बनाने के तीन विकल्प हैं। वे विपक्षी गठबंधन के कुछ दलों या सांसदों को अपने साथ लाकर बहुमत जुटा सकते हैं। हालांकि, चुनाव में विपक्षी दलों ने उन्हें सत्ता से हटाने के मुद्दे पर समर्थन मांगा था। ऐसे में उनके साथ सरकार बनाना राजनीतिक रूप से कठिन हो सकता है।

दूसरा विकल्प आइजनकोट और उनके सहयोगियों के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाना है। इसमें अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियां साथ मिलकर सरकार चलाती हैं। नेतन्याहू प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं और विपक्षी नेताओं को सत्ता में भागीदारी मिल सकती है। लेकिन आइजनकोट चुनाव में नेतन्याहू को हटाने के वादे के साथ उतरे थे, इसलिए यह रास्ता भी आसान नहीं है।

तीसरा विकल्प अल्पमत सरकार बनाना है। इसके लिए नेतन्याहू को सरकार में शामिल हुए बिना समर्थन देने वाले दलों की मदद लेनी होगी। ऐसी सरकार को बजट, विश्वास मत और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए बार-बार दूसरे दलों का समर्थन जुटाना पड़ता है।

आइजनकोट के सामने अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने का विकल्प है।

ढाई गुना वेतन की माँग पर कपड़ा मजदूरों का हिंसक प्रदर्शन, ढाका सहित तीन क्षेत्रों में 670 कारखाने बंद



ढाका, एजेंसी: बांग्लादेश में न्यूनतम वेतन ढाई गुना बढ़ाने की मांग को लेकर कपड़ा मजदूरों का प्रदर्शन सोमवार को हिंसक हो गया। कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों की सुरक्षाकर्मियों से झड़प हुई। मजदूरों ने सड़कें और राजमार्ग जाम किए तथा पुलिस की गाड़ियों सहित कई वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया।

प्रदर्शन के कारण ढाका, गाजीपुर और मयमनसिंह में करीब 670 कारखाने बंद रहे। रविवार को भी 529 कारखानों में कामकाज ठप था। गाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र से गुजरने वाले ढाका-टांगाइल राजमार्ग को प्रदर्शनकारियों ने जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस की तीन गाड़ियों और कई अन्य वाहनों में आग लगाई गई। ढाका से नारायणगंज जाने वाली सड़क पर भी रास्ता रोका गया और टायर जलाए गए। इन घटनाओं में सीमा रक्षक बल के कम से कम दो जवान और कई अन्य लोग घायल हुए। घायलों में पत्रकार भी शामिल हैं। गाजीपुर के औद्योगिक क्षेत्र में सीमा रक्षक बल की 10 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। जिले में सोमवार को 150 से अधिक कारखाने बंद रहे। ढाका पुलिस ने पिछले दो दिनों में तोड़फोड़ और हिंसा के आरोप में कम से कम 14 कारखाना मजदूरों तथा अवामी लीग के नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। रविवार को हुई हिंसा में करीब 50 लोग घायल हुए थे, जिनमें लगभग 15 पुलिसकर्मी शामिल थे। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने रविवार शाम मंत्रियों और सलाहकारों के साथ आपात बैठक की। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े कुछ कारखाना मालिक हिंसा भड़का रहे हैं।

नौसेना को मिलेंगे आठ नए युद्धपोत, 53,866 करोड़ का समझौता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय नौसेना के लिए आठ नई पीढ़ी के युद्धपोत बनाए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने इनके निर्माण के लिए 53,866.50 करोड़ रुपये के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आधुनिक मिसाइल, हथियार और संवेदक प्रणालियों से लैस इन युद्धपोतों का निर्माण दो भारतीय कंपनियां करेंगी। कोलकाता की गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड पांच और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड तीन युद्धपोत बनाएगी। सोमवार को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये युद्धपोत नई पीढ़ी के कॉर्वेट होंगे। करीब दो हजार टन वजन वाले कॉर्वेट तेज गति से चलने के लिए बनाए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इन युद्धपोतों में आधुनिक मिसाइल, हथियार और संवेदक प्रणालियां लगाई जाएंगी। इनकी मदद से नौसेना हवा, समुद्र की सतह और पानी के नीचे से आने वाले खतरों का मुकाबला कर सकेगी। इनका इस्तेमाल समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा, दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ कार्रवाई तथा तटीय सुरक्षा के लिए किया जाएगा। ये समुद्र के किनारे सैन्य अभियान चलाने और निगरानी रखने में भी मदद करेंगे। परियोजना में 70 प्रतिशत से अधिक सामग्री भारत में निर्मित होगी। इन युद्धपोतों का डिजाइन भी भारतीय नौसेना तैयार करेगी। इन्हें वर्ष 2030 तक नौसेना को सौंपने का लक्ष्य रखा गया है। यह परियोजना आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का हिस्सा है।

ट्रम्प रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को पद से हटा सकते हैं

वॉशिंगटन, एजेंसी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ को पद से हटा सकते हैं। अमेरिकी पत्रिका 'द अटलांटिक' की रिपोर्ट के मुताबिक, हेगसेथ ने ट्रम्प को ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया था। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि युद्ध कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन आठ महीने बाद भी संघर्ष जारी है। अब ट्रम्प यह पता लगाने में जुटे हैं कि युद्ध लंबा खिंचने के लिए कौन जिम्मेदार है। रिपोर्ट के अनुसार, ट्रम्प अपने करीबी सहयोगियों से रक्षा मंत्री हेगसेथ और अमेरिकी सेना के संयुक्त प्रमुखों की समिति के अध्यक्ष जनरल डैन केन के कामकाज पर राय ले रहे हैं। दोनों युद्ध को लेकर ट्रम्प के प्रमुख सलाहकार रहे हैं। व्हाइट हाउस के कई अधिकारी हेगसेथ को पसंद नहीं करते। कुछ सहयोगियों का मानना है कि वे राष्ट्रपति को युद्ध की वास्तविक स्थिति बताने के बजाय उन्हें खुश रखने वाली जानकारी दे रहे हैं। हालांकि, रक्षा विभाग के प्रवक्ता सीन पार्नेल ने आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि हेगसेथ राष्ट्रपति और वरिष्ठ अधिकारियों को सैन्य कार्रवाई की पूरी जानकारी देते हैं।

ट्रम्प को आशंका है कि ईरान युद्ध का असर मध्यावधि चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की जीत पर पड़ सकता है।

बदलाव शोध में सामने आया तापमान घटने का रुझान

बदल गया इंसानी शरीर, औसत तापमान घटकर 36.4 डिग्री

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: करीब 150 साल पहले इंसान के शरीर का औसत तापमान आज की तुलना में अधिक था। तब 37 डिग्री सेल्सियस को सामान्य तापमान का मानक माना जाता था, लेकिन हाल के कई शोध में स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान घटकर करीब 36.4 डिग्री पाया गया है। वैज्ञानिक इस बदलाव की वजह समझने की कोशिश कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, इसके पीछे पुराने समय में तापमान मापने के तरीके और बेहतर स्वास्थ्य तथा बदलती जीवनशैली, दोनों की भूमिका हो सकती है।

1860 के दशक में जर्मनी के डॉक्टर कार्ल वंडरलिच ने बुखार और शरीर के तापमान पर अध्ययन किया था। करीब 15 साल तक उन्होंने 25 हजार मरीजों के तापमान मापे और 10 लाख से अधिक आंकड़े जुटाए। इनके आधार पर उन्होंने स्वस्थ वयस्कों का औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस बताया। 38 डिग्री से ऊपर के तापमान को बुखार का संकेत माना गया। बड़े आंकड़ों के कारण 37 डिग्री सामान्य तापमान का मानक बन गया।

स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की संक्रामक रोग विशेषज्ञ जूली पार्सोनेट की टीम ने अमेरिका के करीब 1.90 लाख लोगों के



तापमान से जुड़े 1862 से 2017 तक के आंकड़ों का अध्ययन किया। शोध के मुताबिक, आज अमेरिकी वयस्कों का औसत तापमान करीब 36.39 डिग्री है। 19वीं सदी की शुरुआत की तुलना में अमेरिकी पुरुषों का तापमान लगभग 0.59 डिग्री घटा है।

यह बदलाव केवल विकसित देशों तक सीमित नहीं है। अमेजन के जंगलों में रहने वाले त्सिमाने समुदाय का औसत तापमान 2000 के शुरुआती वर्षों में 37 डिग्री था, जो 2018 तक घटकर 36.5 डिग्री रह गया। इस दौरान उनके रहन-सहन में भी बदलाव आया।

विशेषज्ञों के अनुसार, तापमान घटने की संभावित वजहों में बेहतर स्वास्थ्य और इलाज, साफ-सफाई तथा टीकाकरण शामिल हैं। पहले टीबी, पेचिश और दांतों तथा हड्डियों के गंभीर संक्रमण जैसी बीमारियां अधिक आम थीं। संक्रमण से लड़ने में शरीर ज्यादा ऊर्जा खर्च करता था और गर्मी पैदा होती थी। बेहतर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं से ऐसी बीमारियां कम हुई हैं। साफ-सफाई और टीकाकरण से भी संक्रमण घटे हैं। त्सिमाने समुदाय में जूते और शौचालयों का इस्तेमाल बढ़ने से हुकवर्म संक्रमण कम हुआ है।

घर और दफ्तरों में तापमान नियंत्रित रखने की सुविधा भी शरीर को तापमान बनाए रखने के लिए कम मेहनत करने देती है। हालांकि, पुराने कांच के थर्मामीटर की माप आधुनिक उपकरणों से करीब दो डिग्री अधिक हो सकती थी। पुराने समय में बगल में तापमान मापा जाता था, जबकि आज आमतौर पर मुंह से मापा जाता है।